laid on the Table of the House on the 24th July, 1984."

MR. CHAIRMAN : Motion moved :

"That this House takes note of the Report of the Eighth Finance Commission together with Memorandum showing action taken thereon, laid on the Table of the House on the 24th July, 1984."

There are some amendments given notice of.

SHRI CHITTA BASU (Barasat) : Sir, I beg to move :

That in the motion—

add at the end—

"and urges upon the Government to give effect to the recommendations of the Commission from April, 1984." (1)

PROF. AJIT KUMAR MEHTA (Samastipur) : Sir, I beg to move :

That in the motion—

add at the end—

"and regrets that it has failed to suggest structural remedy for debt relief to the States in respect of overdrafts."(2)

That in the motion—

add at the end—

"and regrets that the Union Government has departed from the accepted principle of treating the Commission's Report as an award in respect of revenue shares and grants-in-aid." (3)

That in the motion—

add at the end—

"and regrets that there is no synchronization of the Finance Commission's quinquennium with the Seventh Plan period so as to enable the Centre and the States to have a complete picture of their respective Plan resources." (4)

That in the motion—

add at the end—

"and its failure to link railway earnings from passenger fares as the States are expected to provide a variety of supporting services for passenger traffic." (5)

MR. CHAIRMAN : Shrimati Geeta Mukherjee is not present.

Some Hon. Members have requested that discussion on the Motion and the Amendments moved thereto may be taken up at a later date and that the other items of business listed in the Agenda may be taken up now. If the House agrees.....

SEVERAL HON. MEMBERS : Yes.

MR. CHAIRMAN : So, it is agreed.

15.35 hrs.

DEMANDS FOR GRANTS (PUNJAB) 1984-85

MR. CHAIRMAN : Now we take up item No 10—Discussion and voting on the Demands for Grants in respect of the Budget for the State of Punjab for 1984-85.

Motion moved :

"That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the Fourth column of the Order Paper, be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Punjab to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1985, in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against Demands 1 to 41."

Demands for Grants in respect of the Budgel for the State of Punjab for 1984-85

Demands for Grants-Budget (Punjab) for 1984-85 Submitted to the Vote of the House

No. of Demand	Name of Demand	Amount of Demand for Grant on Account Voted by the House on 19th March, 1984		Amount of Demand for Grant submitted to the Vote of the House	
		Revenue	Capital	Revenue	Capital
1	2	3		4	
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
1.	State Legislature ...	55,42,000	...	55,43,000	...
2.	Council of Ministers ...	43,82,000	...	43,83,000	...
3.	Administration of Justice ...	2,25,18,000	...	2,25,19,000	...
4.	Elections ...	66,20,000	...	66,19,000	...
5.	Revenue ...	5,43,54,000	...	5,43,54,000	...
6.	Excise and Taxation ...	2,87,70,000	...	2,87,70,000	...
7.	Finance ...	22,81,76,000	...	22,81,76,000	...
8.	Public Service Commission ...	9,32,000	...	9,33,000	...
9.	Civil Secretariat ...	2,40,96,000	...	2,40,95,000	...
10.	District Administration ...	3,32,88,000	...	3,32,88,000	...
11.	Police ...	24,93,47,000	...	24,93,46,000	...
12.	Jails ...	1,97,63,000	...	1,97,62,000	...
13.	Stationery and Printing ...	2,19,76,000	9,20,000	2,19,77,000	9,20,000
14.	Miscellaneous Services ...	2,52,86,000	...	2,52,87,000	...
15.	Rehabilitation, Relief and Resettlement ...	30,60,000	...	30,59,000	...
16.	Education ...	91,44,12,000	...	91,44,11,000	...
17.	Technical Education, Science and Technology ...	1,01,32,000	5,25,000	1,01,31,000	5,25,000
18.	Medical and Public Health ...	35,73,23,000	50,00,000	35,73,23,000	50,00,000
19.	Housing and Urban Development	1,23,38,000	3,81,96,000	1,23,38,000	3,81,97,000
20.	Information and Publicity ...	91,00,000	...	91,00,000	...
21.	Tourism and Cultural Affairs ...	29,06,000	12,50,000	29,07,000	12,50,000
22.	Labour, Employment and Industrial Training ...	4,26,93,000	8,41,000	4,26,93,000	8,42,000
23.	Social Security and Welfare ...	13,18,64,000	82,00,000	13,18,64,000	82,00,000
24.	Planning and Statistics ...	70,69,000	...	70,69,000	...
25.	Co-operation ...	3,27,86,000	4,64,83,000	3,27,86,000	4,64,83,000

1	2		3		4	
26.	Agriculture	...	14,43,66,000	1,54,00,000	14,43,66,000	1,54,00,000
27.	Soil and Water Coservation	...	1,95,75,000	...	1,95,75,000	...
28.	Food	...	73,56,000	4,36,14,20,000	73,56,000	...
29.	Animal Husbandry	...	6,25,62,000	...	6,25,62,000	...
30.	Dairy Development	...	29,55,000	...	29,54,000	...
31.	Fisheries	...	46,41,000	...	46,41,000	...
32.	Forests	...	5,51,48,000	...	5,51,48,000	...
33.	Community Development	...	21,79,88,000	...	21,79,89,000	...
34.	Industries	...	5,50,60,000	3,81,00,000	5,50,60,000	3,81,00,000
35.	Civil Aviation	...	22,35,000	4,00,000	22,34,000	4,00,000
36.	Roads and Bridges	...	11,56,62,000	11,15,00,000	11,56,63,000	11,15,00,000
37.	Road Transport	...	33,09,37,000	4,50,00,000	33,09,36,000	4,50,00,000
38.	Multipurpose River Projects	...	5,92,35,000	15,83,08,000	5,92,35,000	15,83,08,000
39.	Irrigation, Drainage and Flood Control	...	30,29,83,000	21,34,76,000	30,29,83,000	21,34,75,000
40.	Buildings	...	25,73,31,000	6,92,98,000	25,73,31,000	6,92,98,000
41.	Loans and Advances by the State Government	...		... 1,30,16,67,000		... 1,30,16,66,000

MR. CHAIRMAN : Shri Ramavatar Shastri.

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति महोदय, इस सदन ने पंजाब में जो वर्तमान स्थिति है, उसके बारे में विस्तार के साथ और गंभीरतापूर्वक विचार किया है। उस बहस के दौरान पंजाब में साधारण स्थिति कैसे पैदा की जा सकती है, इसके बारे में हमारे दल के नेता माननीय श्री इन्द्रजीत गुप्त ने अपने विचार आपके सामने रखे थे।

15.36 hrs.

[SHRI F.H. MOHSIN *in the Chair*]

पंजाब की जनता के जीवन से संबंधित सवालों को लेकर जो बजट की 41 मांगें पेश की गई हैं, उनमें से कुछ मांगों की चर्चा करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं मांग संख्या-11 जो पुलिस के संबंध में है, उसकी चर्चा करना चाहूंगा। वह मांग 49,89,76,000 रुपए की मांग है। इसका मैं विरोध करना चाहता हूं और उस विरोध का कारण आपके सामने रखना चाहता हूं। श्वेत-पत्र में इस बात को स्वीकार किया गया है कि पुलिस व्यवस्था पंजाब में पिछले कुछ महीनों से लुंज-पुंज हो चुकी थी। उनके बीच में कोई व्यवस्था ही नहीं रह गई थी। वे आतंकवादियों को नियंत्रित करने में बिल्कुल नाकामयाब ही नहीं थे बल्कि उनके साथ सांठ-गांठ कर रखी थी। जो कुछ

भी वे करना चाहते थे, उसको करने की उनको छूट देते थे या कनाइव करते थे। आतंकवादियों की हिंसा की वारदातों को रोकने में वे बिल्कुल असमर्थ साबित हुए। पुलिस विभाग के अधिकारियों की मिली-भगत सीमा पर, तस्करों के साथ थी। उनको इधर-उधर आने-जाने से रोक नहीं पा रहे थे। यह व्यवस्था वहां बिल्कुल छिन्न-भिन्न हो चुकी थी, इसके बावजूद सरकार वहां इतना पैसा खर्च करना चाहती है। यह नहीं बताया गया है कि इन पैसों का उपयोग करके सरकार पुलिस व्यवस्था में कोई नए सिरे से परिवर्तन लाना चाहती है या नहीं। अगर नयी व्यवस्था नहीं बनायेंगे तो इतना पैसा देना बेकार है। जिन लोगों ने गड़बड़ी की है, उनके खिलाफ जांच-पड़ताल होनी चाहिए कि उनकी गलतियां कहां थीं? उन्होंने कहाँ देश के खिलाफ काम किया और कैसे पृथकतावादियों की मदद की, इसकी जाँच होनी चाहिए ताकि उनके खिलाफ समुचित कार्यवाही की जा सके। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और पुलिस पर ज्यादा-से-ज्यादा धन खर्च करने की व्यवस्था करते हैं तो यह मुनासिब नहीं होगा।

नये सिरे से अच्छी तरह पुलिस व्यवस्था को वहां खड़ा करने की जरूरत है। अगर इसकी तरफ सरकार ध्यान नहीं देगी तो जाहिर बात है, वहां की स्थिति में सुधार लाने में पुलिस की जो भूमिका होनी चाहिए, वह उसको अदा नहीं कर सकेगी। हम सभी जानते हैं कि वहां सेना बहुत दिनों तक नहीं रह सकती। वैसे सेना की वापसी की मांग हम विरोधी दल के कुछ लोग सरकार से करने जा रहे हैं कि स्वर्ण मन्दिर परिसर से सेना को हटाया जाना चाहिए, लेकिन सरकार अभी उसके लिए तैयार नहीं है। फिर भी इतना तो स्पष्ट है कि आप बराबर स्थाई रूप से सेना वहाँ नहीं रखेंगे और पुलिस के बल पर ही आपको निर्भर रहना होगा। जब ऐसी स्थिति होगी तो जाहिर बात है, हमारा पुलिस बल हिम्मत रखने वाला हो, देश-भक्त हो, आतंकवादियों के चंगुल में किसी तरह न जा सके, पृथकतावादियों के खिलाफ डटकर लोहा लेने वाला हो, तभी वह सारे कामों को सही ढंग से अंजाम दे सकेगा। उसमें सारी सामर्थ्य होनी चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि जहां आप पुलिस बल को मजबूत करने पर इतना पैसा दे रहे हैं, लेकिन पुलिस संगठन को आगे किस तरह से चुस्त-दुरुस्त करना है, क्या इस बारे में भी आपकी कोई योजना है। सदन जानना चाहेगा कि आप किस तरह से उनको पुनर्गठित करना चाहते हैं, उनको किस तरह से अपने पांवों पर खड़ा करना चाहते हैं, कानून और व्यवस्था उनसे किस तरह से करवाना चाहते हैं। आपको इन सारी बातों की जानकारी सदन को देनी चाहिए। इसके साथ ही यह भी बताया जाना चाहिए कि जिन लोगों ने आतंकवादियों के साथ, पृथकतावादियों के साथ, राष्ट्र-द्रोह के कामों में हिस्सा लिया, उनके खिलाफ जांच करके आप क्या कार्यवाही करना चाहते हैं।

दूसरा निवेदन मैं कृषि के सम्बन्ध में करना चाहता हूं। इस आन्दोलन के फलस्वरूप वहां की कृषि व्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ा है और वह अस्तव्यस्त हो गई है। जहां पहले पंजाब में बाहर से लाखों लोग आकर वहां फसलों की कटाई-बोआई में काम करते थे, इस आन्दोलन की वजह से वे इस बार नहीं आ सके। खुद हमारे सूबा बिहार से लाखों लोग आते थे, जिसका सबूत हम रेलगाड़ियों की छतों पर सफर करते लोगों को देखते थे, जहां उनको बैठने तक की जगह नहीं मिलती थी, उसके बावजूद जैसे-तैसे करके वे लोग पंजाब आते थे। पंजाब के किसानों की मदद करते थे जिसके कारण वहां के किसानों की आर्थिक दशा अच्छी हो गई थी। सारी फसल की बोआई और कटाई का सारा काम उनके जिम्मे था। वहां

के किसान अपनी अच्छी उपज के द्वारा हिन्दुस्तान की जनता की भूख मिटाने की कोशिश करते थे तथा स्वयं के लिए और सरकार को भी ज्यादा-से-ज्यादा गल्ला देते थे। मगर इस आन्दोलन के कारण इसमें भी रुकावट आई है। मैं चाहता हूं कि कृषि व्यवस्था में जो कमी आई है, सरकार को उसे ठीक करने की तरफ ध्यान देना चाहिए तथा किसानों को फिर से अपने पांवों पर खड़ा करने में सहायता देनी चाहिए।

खेतों में काम करने वाले मजदूरों पर भी इस आन्दोलन का प्रभाव पड़ा है, उनकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। इतना ही नहीं, वहां के किसानों को लाभकारी मूल्य भी मिलना चाहिए। लेकिन हमारी सरकार किसानों को लाभकारी मूल्य देने से हिचकती है। जो दाम वह तय करती है, उसी को कहा जाता है कि यह लाभकारी मूल्य है। इसलिए इस आन्दोलन के दौरान किसानों की जो स्थिति बिगड़ी है, उनकी बिगड़ी हुई स्थिति में सुधार लाने का प्रयास होना चाहिए ताकि वहां का किसान फिर से पहली स्थिति में आ सके और पूरे हिन्दुस्तान के लोगों को गल्ला उपलब्ध करवा सके। कृषि व्यवस्था में आई गड़बड़ी को भी सही रास्ते पर लाने में सरकार को योजना बनाकर सहायता देनी चाहिए तथा पैसे का प्रावधान करना चाहिए।

अंत में सभापति जी मैं सामाजिक सुरक्षा और कल्याण विषय पर कुछ कहना चाहता हूं। इस मद में मेरे ख्याल से अधिक पैसे का प्रावधान करने की जरूरत है क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। हम पंजाब की बात नहीं जानते, लेकिन हमारी स्टेट में लाखों वृद्धा लोगों को पेंशन देने की सरकार ने व्यवस्था की है, हालांकि वह बहुत कम है। 30 रुपये महीना जो देते हैं, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसे बढ़ाया जाना चाहिये।

भ्रष्टाचार तो अपनी जगह पर है, लेकिन जो पैसा देते हैं वह बहुत कम है। आज 30 रुपये की कीमत क्या हो सकती है। हम लोग रोज 75 रुपये लेते हैं लेकिन आप खेत-मजदूर को वृद्धावस्था में या बेवाओं को 30 रुपये महीना देते हैं, यह बिहार में है। पंजाब में कोई व्यवस्था है या नहीं, लेकिन सामाजिक सुरक्षा विभिन्न रूप में देनी चाहिये।

पंजाब में जिन्होंने देश की सुरक्षा में कुर्बानी की है, आज भी कर रहे हैं और मेरे ख्याल से बराबर कुर्बानी करते रहेंगे, तो जब वह रिटायर हो जाते हैं तो उनको पेंशन देते हैं, दूसरी सहूलियतें देते हैं। मेरे ख्याल में उनको और सहूलियतें दी जानी चाहियें, उनकी पेंशन में वृद्धि करनी चाहिये। इस मद में आप ज्यादा धन रखेंगे तभी आप विभिन्न प्रकार की सामाजिक सुरक्षा के कार्यों को कर सकेंगे। अभी पंजाब की स्थिति को सामान्य बनने में समय लगेगा और इसके लिए ज्यादा धन की जरूरत पड़ेगी। आपको इन बातों की तरफ ध्यान देना चाहिये।

मुझे यही 2-3 बातें आपके सामने निवेदन करनी थीं।

MR. CHAIRMAN : I wish to inform the Hon. Members that the time allotted for this item is only one hour. I would therefore request the Hon. Members to be as brief as possible.

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : सभापति महोदय, पंजाब के सम्बन्ध में पेश की गई अनुदानों की मांगों का मैं समर्थन करते हुए कुछ बातें कहना चाहता हूं।

इसमें मंत्रि-परिषद् के सम्बन्ध में जो खर्चा निश्चित किया गया है, तो मंत्रि-परिषद् इस समय है नहीं, यह कब अपना कार्य करेगी ? मैं चाहूंगा कि यह जल्दी अपना कार्य करे, इस सम्बन्ध में भारत सरकार निश्चित करे।

निर्वाचन के सम्बन्ध में 132 लाख 39 हजार की राशि रखी गई है। यह कौन से चुनाव पर खर्च किया जायेगा ?

पुनर्वास और राहत कार्यों के बारे में जो 61 लाख 19 हजार की मांग रखी गई है, क्या यह उन लोगों के लिये है जो वहां घटना-चक्र इस समय चला उसमें परेशान हुए या उजड़े या यह किसी और मद में खर्च किया जायेगा ?

पुलिस के बारे में श्री शास्त्री जी ने जो बात कही, यह सही है कि जनता पार्टी के शासन में पुलिस के अन्दर की गई भर्ती में सुधार लाने की आवश्यकता है। पंजाब में जो अकाली सरकार थी, उसमें सुधार लाने सम्बन्धी सरकार क्या करने जा रही है ?

उग्रवादी सिखों के द्वारा जो गतिविधियां चलीं, उस संघर्ष में जिन पुलिस कर्मचारियों ने अपने जीवन की बलि दी है, उनके परिवारों के सम्बन्ध में सरकार ने क्या योजना बनाई है ? उग्रवादियों को स्वर्ण मंदिर में से निकालने में जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, उनके परिवारों को राहत पहुंचाने के सम्बन्ध में इसमें कोई बात नहीं कही गई है। यह पंजाब का बजट है और इन लोगों ने पंजाब के लिये ही बलिदान दिया है। स्वर्ण मंदिर के लिये हिन्दू और सिख एकता को दृष्टि में रखते हुए, राष्ट्रीय अखंडता को ध्यान में रखते हुए हर प्रान्त के सैनिक नौजवानों ने उसमें अपना बलिदान दिया है।

हमारा डिफेंस विभाग इस बारे में कुछ करेगा, लेकिन पंजाब सरकार का भी यह दायित्व है कि वह उन सैनिकों के परिवारों की सहायता करे। इस विधेयक में उसका कोई उल्लेख नहीं है। मंत्री महोदय यह स्पष्ट करें कि विभिन्न प्रान्तों के हमारे जो सैनिक शहीद हुए हैं, उनके परिवारों को सहायता देने के लिए क्या कोई योजना बनाई गई है, यदि हां, तो वह पेश करनी चाहिए।

अकाली सरकार ने पंजाब के सभी विभागों में बहुत मनमानी और अव्यवस्था की स्थिति पैदा कर दी थी। कई कार्पोरेशनों में केवल एक जाति के लोग चैयरमैन बनाए गए और उन्हीं लोगों को अंधाधुन्ध भरती कर दिया गया। पंजाब में अन्य जाति, वर्ग और विचारधारा के योग्य लोग भी रहते हैं। उनकी सेवाओं से लाभ उठाया जाना चाहिए। केवल एक जाति के लोगों को सारे कार्पोरेशन्ज का चैयरमैन बना दिया जाए, यह उचित प्रतीत नहीं होता। पंजाब में हिन्दू, सिख, आर्य समाजी, सनातनी, निरंकारी और राधास्वामी आदि सब रहते हैं। सरकारी विभागों और कार्पोरेशन्ज की सेवाओं के लिए नियुक्तियां करते हुए उनमें बैलेंस रखना चाहिए। वह बैलेंस अकाली सरकार के समय टूट गया था। क्या सरकार उसमें कोई सुधार लाना चाहती है या नहीं ? मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इन बातों का स्पष्टीकरण करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : सभापति महोदय, पजाब विनियोग विधेयक, 1984 में 41 मदों में भिन्न-भिन्न राशियां दी गई हैं। मेरे पूर्ववक्ताओं ने पुलिस आदि की तरफ इशारा किया है। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि यह संसद पंजाब के बजट को पास कर रही है। सरकार को जितनी जल्दी हो सके, वहां की स्थिति को सामान्य बनाने की कोशिश करनी चाहिए। पंजाब में राष्ट्रपति शासन या केन्द्र सरकार का शासन लम्बे समय तक रहना हमारे लिए खतरे का कारण बन सकता है। सरकार कोशिश करे कि या तो विधान सभा को बहाल किया जाए या दोबारा चुनाव करा के लोकप्रिय सरकार की स्थापना की जाए।

पंजाब में आज जो स्थिति है, उसके बारे में यहां पर कई बार चर्चा हो चुकी है। लेकिन फौज के बल पर पंजाब में ज्यादा दिनों तक सामान्य स्थिति नहीं बनाए रखी जा सकती है। मैं मांग करता हूं कि जितनी जल्दी हो सके, फौज को वहां से वापस बुलाया जाए और वहां पर सामान्य स्थिति पैदा की जाय। शासन फौज के हाथ में हो और पुलिस पर भी विश्वास न रहे, दीर्घकालीन दृष्टि से यह स्थिति अच्छी नहीं है।

हमारे जो फौजी स्वर्ण मंदिर में से उग्रवादियों को निकालते हुए शहीद हुए हैं, उनके परिवारों को कोई-न-कोई राहत देने के लिए इस बजट में प्राविजन करना चाहिए। इस सरकार की गलत नीतियों के कारण, उसके द्वारा देर से कदम उठाने के कारण, हमारे जो भाई वहां पर शहीद हुए हैं, उनके परिवारों को सहायता देने के लिए विशेष तौर पर प्राविजन करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा, तो हमारी फौज का मोराल गिरेगा।

जो मंदिर तोड़े गये हैं, उनकी मरम्मत की व्यवस्था की जानी चाहिए। अगर अकाली इसके लिये तैयार हैं, तो उसके लिये भी सहायता-कार्य करना चाहिये। लेकिन जिस ढंग से संतासिंह को सरकार ने वहां ले जाने और कार-सेवा कराने का काम किया है उससे आप पंजाब की स्थिति को सामान्य नहीं बना पायेंगे। आपने उनको वहां पर ले जाकर जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। इससे आप देश की एकता और अखण्डता को नहीं बचा पायेंगे। आप वहां पर सिखों द्वारा, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्यों द्वारा कार-सेवा चलाने का काम करें वरना स्थिति यह होगी कि आज संतासिंह के द्वारा अकाल तख्त का निर्माण किया जा रहा है, वे इसका निर्माण करेंगे और कल जब गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वहां पर आयेगी तो वे लोग इसको गिराने का काम करेंगे और फिर उसको बनायेंगे। तो यह गिराने और बनाने का जो काम होगा वह हमारे लिये अच्छा नहीं होगा। संतासिंह कहते हैं कि पुनर्निर्माण होगा और सिखों के दूसरे प्रतिनिधि कहते हैं कि यदि इसका निर्माण किया गया तो उसको गिराकर फिर निर्माण किया जायेगा। इस प्रकार से एक संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई है। इसका कारण यह है कि आपने सिखों को अपने विश्वास में नहीं लिया है।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि पंजाब के उद्योग-धंधों पर इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। बहुत से मालिक अपने उद्योगों को पंजाब में छोड़कर चले आये हैं, क्योंकि उनको वहां पर चैन से काम ही नहीं करने दिया गया। इसके कारण पंजाब में औद्योगिक प्रोडक्शन में बहुत गिरावट आई है। मेरा निवेदन है कि सरकार प्रोटेक्शन देकर उनके उद्योगों को वहां पर चलवाने का काम करे ताकि औद्योगिक प्रोडक्शन बढ़ सके। सरकार उनको बैंकों से सही रूप में सहायता भी दिलाने की व्यवस्था करे वरना इस देश की जो अर्थ व्यवस्था है, जिसकी बैंक-बोन पंजाब है, वह टूट जायेगी। लुधियाने की जो हौजरी का उद्योग है वह भी बहुत अधिक प्रभावित हुआ है। इस उद्योग को भी पुनरुज्जीवित करने के लिये आप इस बजट में अच्छे प्राविजन लायें वरना पंजाब और इस देश की अर्थ व्यवस्था सुधर नहीं पायेगी। मैं ज्यादा न कहते हुये यही कहना चाहता हूं कि आप उद्योगों के ऊपर खास नजर रखें।

इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पंजाब की कृषि पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। वहां के जो इन्नोसेंट किसान हैं—हिन्दू या सिख—वे अपने खेतों और ट्यूबवैलों पर जाकर काम नहीं कर पाये हैं। खेती के सम्बन्ध में एक समस्या यह भी

रही है कि उसमें जो फिजिकल काम करने वाला लेबर है वह पंजाब का नहीं है बल्कि बिहार और उत्तर प्रदेश से वहां पर जाता था लेकिन इस बार वह वहां पर नहीं जा पाया है। इस कारण भी पंजाब की कृषि प्रभावित हुई है। मेरा निवेदन है कि उस लेबर को सरकार की ओर से गारंटी देकर वहां पर भेजकर काम कराने की व्यवस्था की जाए।

PROF. N. G. RANGA (Guntur): Protected by whom ? Not by the Army and not by the Police.

श्री जगपाल सिंह : आप बाद में जवाब दीजिएगा।

आज वहां पर मजदूर जाने के लिए तैयार नहीं है। बिहार और उत्तर प्रदेश के मजदूर वहां नहीं जा रहे हैं। डेढ़ साल से वहां पर मजदूर नहीं गया है। इस वजह से वहां की कृषि भी प्रभावित हुई है और लाखों मजदूर भी अपने बच्चों का पेट पालने से महरूम हुये हैं।

प्रो० सत्यदेव सिंह : इसके लिये उत्तरदायी कौन है ? इसका उत्तरदायित्व जनता सरकार पर है।

(व्यवधान)

श्री जगपाल सिंह : इसके लिए आपकी पार्टी और आपकी सरकार जिम्मेदार है। भिण्डरावाले को पैदा करने वाले आप हैं। स्वर्ण मंदिर में आज जो भी स्थिति पैदा हुई है उसकी सारी जिम्मेदारी आप पर है। जिस स्थिति में आज वहां पर फौज भेजनी पड़ी है उसकी सारी जिम्मेदारी आपकी पार्टी और सरकार पर ही है। इसका कारण यह है कि आपने समय पर कोई कदम ही नहीं उठाया।

(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Why are you so impatient ? You will have your own turn, and you can reply to him. Please be patient.

16.00 hrs.

श्री जगपाल सिंह : ऐसी बात इसमें नहीं लानी चाहिए। जिस प्रकार की स्थिति वहां पैदा हो रही है, उसको हम भी मानते हैं और आप भी मानते हैं कि हमारे देश की एकता और अखंडता को तोड़ने के पीछे साम्राज्यवादी ताकतें हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि यदि सरकार उचित कदम उठाती तो यह स्थिति पैदा न होती। इस परिस्थिति का मुकाबला रूलिंग पार्टी और विरोधी दलों को इकट्ठे होकर करना पड़ेगा।

सभापति जी, मैं अपनी बात खत्म करते हुए उन साम्राज्यवादी ताकतों से कहना चाहता हूं कि वे हिन्दुस्तान में अपोजीशन और रूलिंग पार्टी में मतभेद पैदा करके मुल्क को नहीं तोड़ सकते हैं। अगर उन्होंने तोड़ने की कोशिश की तो हम लोग अपोजीशन और रुलिंग पार्टी के मतभेद को भूलकर उनका मुकाबला करेंगे और उनको दुबारा इस धरती पर नही आने देंगे। इन शब्दों के साथ मैं पुनः बजट में उन फौजी भाइयों के लिए भी प्रोवीजन की मांग करता हूं। कृषि की ओर भी आपको ध्यान देना चाहिए। स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई जो इन्डस्ट्रीज हैं, उनको प्रोटेक्शन देकर बढ़ाने का काम करना चाहिए, तभी आपके इस बजट की मंशा पूरी हो सकती है।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, मैं पंजाब की अनुपूरक मांगें, 1984 जो सदन में प्रस्तुत की गई है, उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

किसी भी देश में और किसी भी प्रान्त में जब तक कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक

नहीं होती है, तब तक उस प्रान्त और देश की प्रगति नहीं हो सकती है । हमारी केन्द्रीय सरकार पंजाब के राष्ट्रपति शासन में जिस प्रकार से काम कर रही है, जो कदम उठा रही है, उसकी प्रशंसा सिर्फ हिन्दुस्तान की जनता ने ही नहीं बल्कि दुनिया ने की है। हमारी प्रधान मंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जो कदम उठाया है, वह ठीक समय पर उठाया है ।

एक तरफ तो विरोधी पार्टियां यह कहती हैं कि अकालियों से समझौता करो और जब हमने समझौता करने की कोशिश की और समझौते में कतई कहीं कोई गुंजाइश नहीं रही तब जाकर हमने यह कदम उठाया है और समय पर उठाया है । कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक ढंग की होगी तो हमारे कृषि उत्पादन और औद्योगिक उत्पादन में जो रुकावट आ रही है, वह दूर हो जाएगी । इस ओर हम धीमें-धीमे प्रगति कर रहे हैं और आज भी यह परिस्थिति है कि पंजाब में उत्पादन बहुत ही अच्छा हुआ है । उत्पादन की दृष्टि से जिस प्रकार का उत्पादन 1982-83 में हुआ, उसको देखते हुए 1983-84 में उत्पादन में कोई कमी नहीं आई है । प्रोक्योरमेंट की दृष्टि से पंजाब हमेशा अग्रणी रहा है, अग्रणी था और अग्रणी रहेगा । इन परिस्थितियों में भी हम कानून और व्यवस्था को कायम रखते हुए, लोगों के अन्दर भय को समाप्त करते हुए, हम आगे बढ़ते गए । यह सही बात है कि जब कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है तो उसका असर पड़ता है, अगर यह स्थिति सही होती तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इन्डस्ट्री प्रोडक्शन और भी ज्यादा होता । इसलिए पंजाब आगे बढ़ रहा है और जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने हिलिंग टच के बारे में कहा है, हमें उसका प्रयास करना चाहिए । हमें किसी को बुरा कहने की नीति में परिवर्तन करना चाहिए ।

हमें सुधार की नीति अपनानी चाहिये । पुलिस की कमजोरियां हमें मालूम हैं, इन्टैलिजेंस की कमजोरियां हमें मालूम हैं और सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने महसूस किया है कि उनमें परिवर्तन होना चाहिये, इसलिये हमको वह परिवर्तन करना चाहिये । पुलिस का जो रेक्रूटमेन्ट हो, उसमें राष्ट्रीय विचारधारा के लोगों को लेने का प्रयास करना चाहिये । स्टेट्स में जो आई०ए०एस० और आई०पी०एस० अफसर हों, उनमें 50 परसेन्ट वहीं के हों और 50 परसेन्ट दूसरी जगह से आयें । सरकार ने इस सम्बन्ध में जिस नीति की घोषणा की थी, उसका इम्प्लीमेन्टेशन करना चाहिये, यह एक बहुत अच्छा कदम है । पहले जब हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस के ट्रांस्फर का मामला आया तो उस समय उसकी बहुत आलोचना की गई थी, लेकिन अब देख रहे हैं, मैं विशेष रूप से अपने राजस्थान के बारे में कह सकता हूं, सभी एडवोकेट्स अब इसको एप्रीशियेट कर रहे हैं और जनता भी इसको एप्रीशियेट कर रही है । हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है, उसमें किसी प्रान्त में केवल उसी प्रान्त के अधिकारी हों, यह उचित नहीं है । उसका बहुत कुप्रभाव पड़ता है और पहले पड़ा भी है । पंजाब में ही जो पंजाब के आई०पी०एस० और आई०ए०एस० आफिसर्स थे, उनको जो भूमिका अदा करनी चाहिये थी, वह उन्होंने अदा नहीं की । इसलिये केन्द्रीय सरकार ने जो निर्णय लिया है, उसके शीघ्र कार्यान्वयन की आवश्यकता है ।

हमारी आर्मी ने पंजाब में जो भूमिका अदा की है और जिस प्रकार से त्याग किया है उसके लिये हमें उनके परिवार के सदस्यों को अधिक-से-अधिक मुआवजा देना चाहिये । वहां की परिस्थिति एक विशेष परिस्थिति थी, उस परिस्थिति में हमारी आर्मी के जो जवान और लैफ्टीनेंट्स सबसे पहले वहां गये, वे मौत के मुंह में गये । इसके लिये उन्हें पूरी तरह से मुआवजा दिया जाना चाहिये ।

हमारी यह कोशिश होनी चाहिये कि हम

उनको पूरा मुआवजा देकर उनको सन्तोष करें।

भाखड़ा की जो मुख्य नहर है उसमें दो बार दरार पड़ी। पहली दरार पाटने में डेढ़ करोड़ रुपये का नुकसान हुआ और दूसरी दरार पर अभी काम चल रहा है। मैंने इस सम्बन्ध में एक प्रश्न पूछा था, मुझे मालूम हुआ है कि सिर्फ हरियाणा के किसानों को इससे 113 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, राजस्थान को जो नुकसान हुआ है, वह अलग है। दोनों दरारें जो डाली गई हैं, वे इस योग्यता के साथ डाली गई हैं, एक्सपर्टस की राय लेकर डाली गई हैं, जिनसे पंजाब का नुकसान नहीं होता है, हरियाणा और राजस्थान का नुकसान होता है। इसकी जांच की जानी चाहिये। इस घटना से हमारे यहां पीने के पानी तथा बिजली पर असर पड़ा है, एग्रीकल्चर में रुकावट आई है। इस नुकसान में हम किसानों की जो भी मदद कर सकते हैं, वह हमें करनी चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आनन्दपुर साहब का जो रेजोल्यूशन है, खालिस्तान का जो नारा है, उन को हमें कतई मन्जूर नहीं करना चाहिये और हमें राष्ट्रीय एकता के लिये पूरी तरह से तैयार होना चाहिये। इस प्रकार की जो साम्प्रदायिक शक्तियां हैं, एक्सट्रीमिस्ट शक्तियां हैं, जो इस प्रकार के नारे लगाती है, उनका पूरी तरह से मुकाबला करना चाहिये। देश हमारे साथ है, देश की जनता हमारे साथ है, हमारा लक्ष्य बहुत महान है, विशाल है, हम अवश्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। पंजाब की प्रगति होगी, विकास होगा, पंजाब ने हमारी बहुत मदद की है, राजस्थान में जो फैमीन कण्डीशन्ज थीं, उनमें पंजाब ने बहुत मदद की है। हम चाहते हैं कि पंजाब की उन्नति हो, विकास हो और वह देश की उन्नति में बहुत सहायक सिद्ध हो।

इन शब्दों के साथ मैं इस बजट तथा फाइनेन्स बिल का समर्थन करता हूं।

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY (Calcutta South) : Mr. Chairman we are discussing today Punjab budget. At the very outset, I like to say that as a democrat it is painful for me to discuss the budget of a State here. Normally our Constitution as our founding fathers made it, a federation Constitution, though with many limitations. But it was expected that the States will run normally and the elected representatives of the people would discuss the economic problems of the State. It is most unfortunate that under compelling circumstances we have to discuss it. Now, the sooner the civil administration is restored, the better. The sooner the elected representatives can function there, the Government can function there, the better for our democratic system. And that is why, at the very outset I would like that the Government should at least withdraw the Army from the Golden Temple itself to create a congential atmosphere and also, I request the Government not to allow a person conduct *kar seva* who is not legally authorised. That will hurt and that is hurting the feelings of our Sikh brothers.

Now, we are discussing Punjab. Punjab is one of the prosperous States of India and I was going through the budgets of Punjab for 1981-82, 1982-83 and 1983-84 It is a revenue surplus State. Also, the per capita income of the people of Punjab is one of the highest. It is all due to its agriculture. Punjab primarily is an agricultural State. Its prosperity depends on agriculture and what it produces today is a result of the green revolution. That we know. But we find in Punjab, unfortunately that in the midst of plenty there is poverty.

I have collected some statistics recently and there I find that in Punjab 10 percent of the farm households control 37.08 per cent of cultivable area. Ten per cent of the people of the farming households owning 38.08 per cent area and mostly comprising more than 20 acres ! And, 41.56 per cent of the farming households own 49.79 percent of the area, and 48.44 per cent of the farming households have small holdings of less than five acres each, and together 13.13 per cent of land,

In the land of greenr evolution we find that majority of the small holders, 45 per cent of the population according to the latest State Government survey, live below the poverty line. So, there is a plenty so far as the rich households are concerned, who are owning more than 20 acres of land. Where is the poverty ? Poverty is there where holding is marginal, less than five acres. Most of the people in Punjab are poor just because they do not have enough land—land being the major source of income. Not only that. It shows that the fruits of green revolution were reaped by the 10 per cent of the farming community. You talk of green revolution of increase in production. It is true that there is a phenomenol growth in production though it has come to a stationary stage now according to the experts. But who are the farming households who can afford this rising cost of inputs ? Only the households which have marketable surplus. Which are those households? Precisely farming households which own more than 20 acres of land. That is why, in Punjab 10 per cent of the people have reaped all the benefits of the green revolution which is so much advertised by the ruling party Members. There has been growth but at the expense of whom ? That is the question which the Minister has to answer.

MR. CHAIRMAN : It is different in Bengal ?

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : We are trying our best. In West Bengal there have been drastic land reforms. The Legislature has passed a Bill to that effect whereby we have drastically reduced the minimum ceiling. That Bill is lying with the Central Government. Compared to Punjab I must submit very humbly that it is better there.

PROF. SATYA DEO SINGH : What is the limit there ?

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : It was 15 acres. Then we have reduced it and the Land Reforms Bill is lying with the Central Government for getting its approval. The moment the Central Government does it, we will be able to introduce these land reforms.

Not only that. It is really amazing and startling revelation that in advance districts like Ludhiana we find that more and more peasants are pushed out of agriculture and in the decade 71-81, the census says that there has been a phenomenal rise in the number of agricultural unemployed and the number of cultivators pushed out of culvitation in Panjab is seven per cent in the decade 1961-71. When the marginal farmers are pushed out, what do they do ? When they do not find any gainful employment in the village because they lose land, they cannot stand the competition—Mr.Ranga, you are an expert, you know that why marginal farmers lose their land and how they join urban proletariat—they create problems in Punjab. The route of extremism if anyone is to find out, he will find it by this uprooting of the village people. They are going to the cities for employment and not finding employment, some of them turn extremists. I am quoting from your figures, the figures given by the Government.

Now, what is the position of unemployment in one of the most advanced States of India ? In 1966, the unemployment of technically trained and professional people was 9,321, it is now 64,771. From 9,000 it has gone up to 64,000. So far as the white-collar people, the clerical posts are concerned, unemployment was 2,713 in 1966, it has gone up to 45,708 in 1981. Then, the total unemployment—I am talking about the registered unemployment only—was 50,578 in 1966, it is 4,86,081 in 1981. So, that is the position in Punjab. Alarming unemployment ! Forty-five per cent of the people are below the poverty line in the so called land of plenty, in the land of Green Revolution. This is precisely because of the fact that without basic land reform, Green Revolution was thrust into Punjab. And if you go through the reports of the United Nations, they have said that this Green Revolution is going to produce social tension. Why ? Why there will be social tension ? Yes, because of Green Revolution, production will go up undoubtedly, they are feeding the people of India undoubtedly, but only a microscopic minority will get all the benefits —people having surplus land, people having enough land—but the poor people are going to suffer. That is given in the United Nations work. And today we find the social tensions in Punjab have their roots in the

Green Revolution itself. This success has become a failure in the sense that it has created social tension and because of this we find the rise of extremism, because there is rise in unemployment, there is frustration. So, this is the position in Punjab.

Now, because of this movement, and I must say because of the peculiar condition that is prevailing in Punjab, there is the question of law and order and unfortunately the State Government could not control it.

What is happening ? Its economy is very much adversely effected. To-day, as my friend was telling, Punjab for its agriculture depends on the labour from U.P., Bihar and other States. These are seasonal workers. They go there during harvesting season, sowing season. But because of the un-settled conditions there, law and order problem there, there has been a significant fall in the flow of labour from these areas to Punjab. They are reluctant to go to Punjab because there is no safety.

I would like to draw the pointed attention of the Finance Minister in Punjab like West Bengal State the credit deposit ratio is such which goes against the interest of the State. The Hon. Minister of Finance will have to look into it. I have the statistics about Punjab.

It is the duty of the Government, as I have said to bring normalcy in Punjab. It is a highly prosperous State, and also it is their duty to go into this problem which I have just mentioned. Until and unless there is land reform, until and unless people feel that they can share the fruits of development, there will always be discontent.

SHRI M. RAM GOPAL REDDY (Nizamabad) : Quite right. We agree with you.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : It is for the Finance Minister to note that because of the rise in price of agricultural inputs, for the marginal and small farmers agriculture is not a profitable proposition. You will have to look to it this rise in cost of inputs is telling upon the economic strength of the marginal farmers.

SHRI M. RAM GOPAL REDDY : We have reduced the price of fertilisers twice in one year.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : These are some of the problems. I want the Minister to formulate the policy of the Govenment.

To conclude, I would demand that very quickly there should be restoration of the democratic Government instead of depending upon the administrative measures.

The other day our Home Minister was telling when the Military entered the golden temple, it was an hour of glory. It was not an hour of glory. It could have been necessity. I do not agree with him. Had appropriate action been taken in time, it could have been avoided. When there is a failure of the administration, when you cannot settle the problem, you have ordered the Army to do something. It is, no doubt their duty to do it. But it signifies the failure of your Government, it signifies the failure of the Central Government. After all the success of the Army does not speak well about the civilian administration in any country. For your internal administration, if you depend on Army, you cannot tell this an hour of glory It is an hour of darkness, darkness in the sense that political...

(*Interruptions*)

SHRI RAM PYARE PANIKA (Robertsganj) : Time and again our Prime Minister inside and outside the House told...

(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : You will also have time to speak on the subject. Please do not interrupt.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : What I say is, it is not an hour of glory. It is a political failure. It is a political disaster. It is a failure of the civilian Government.

It is the failure of the Central Government. And that is why, don't take pride in it. I want, Mr. Chairman, that normalcy should be restored as quickly as possible.

Restoration of democracy should be there and the people of Punjab should determine the destiny of Punjab because the Constitution has given them the right to determine their destiny in their own sphere.

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : सभापति महोदय, मैं शुरू में ही अपने लायक दोस्त को बता देना चाहता हूं, सदन को याद होगा कि माननीय प्रधान मंत्री ने इस सदन में भी और बाहर भी, जब स्वर्ण मंदिर में मिलिट्री का प्रवेश कराना पड़ा तो उन्होंने कहा था कि हमें बड़े भारी दिल से यह आदेश करना पड़ा है। मुझे आश्चर्य है कि हमारे सी. पी. एम. के मित्र आज इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं; यह बात बिल्कुल साफ हो गई है कि किसी को इसमें सुख नहीं था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थीं। माननीया प्रधान मंत्री जी ने वहां पर मिलिट्री का प्रवेश करा कर निश्चित तौर पर एक सामयिक कदम उठाया जिससे न केवल पंजाब की और गुरुद्वारे की पवित्रता ही बचाई बल्कि देश को खडित होने से बचा लिया।

माननीय सदस्य व्हाइट पेपर पर बहस के समय विस्तार से तमाम आलोचना कर चुके हैं, मैं उनसे अपेक्षा करता था कि वह पंजाब के बजट पर बोलेंगे लेकिन वह सारे भारतवर्ष की बात करते हुए अपने बंगाल की तारीफ कर गये। आज सबको मालूम है कि वहां विद्युत् उत्पादन की क्या समस्या है। आप कलकत्ते में जाइये, आपको सब पता लग जायेगा। आप आश्चर्य करेंगे कि केन्द्रीय सरकार के और सेंट्रल इलैक्ट्रिसिटी अथारिटी के होने के बाद the generation of electricity is getting deteriorated day by day in West Bengal.

(*Interruptions*)

आज वहां की इडस्ट्री की हालत क्या है ? वहाँ केवल एक लाभ हो रहा है कि इनके कैडर के लोगों को वहां विभिन्न स्थानों पर नौकरी में रखा जा रहा है। जो गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का काम है, स्वतः रोजगार की बात है, एन.आई.ई.पी., आई.आर.डी.पी. के कार्यक्रम हैं, उनसे इनके कैडर के लोगों को ज्यादा लाभ हो रहा है। यह हकीकत है, अगर इन तथ्यों की जानकारी करनी हो तो यहां से एक कमेटी जा सकती है।

आज पंजाब का बजट एक असाधारण स्थिति में लोक सभा में रखा गया है। ये लोग अकालियों का क्यों समर्थन करते हैं। हम कहते हैं कि देश एक है लेकिन ये सी. पी. आई. और सी. पी. एम. के लोग मल्टी नेशनल में विश्वास करते हैं इसलिये ये अकाली दल से मेल रखते हैं और इन्होंने उनको उकसाया। सोवियत यूनियन और यूनाइटेड अमरिका की तरह हमारा देश नहीं है। हमारा देश एक है, हमारे यहां विभिन्न भाषाएं हैं, कल्चर हैं, लेकिन हमारा कांस्टीट्यूशन एक है।

आपको याद होगा कि जब बहस चल रही थी तो आनन्दपुर के प्रस्ताव पर सबने यह कहा कि हमारा समझौता सारे का सारा हो गया था, लेकिन यह केन्द्र सरकार थी जिसने समझौते का डिक्लेयरेशन नहीं किया।

उन्होंने ऐसा क्यों कहा ? हम इन लोगों की भावना समझ सकते हैं। ये लोग अपने पोलिटीकल लाभ के लिए ऐसा करते हैं।

हम इस बजट का समर्थन करते हैं, लेकिन जैसा कि आचार्य भगवान देव ने कहा है, देश के जो सिपाही हरमंदिर साहब की सैंक्टिटी, पवित्रता, को बचाने के लिए मरे हैं, वित्त मंत्री को उनके परिवारों के लिए कुछ प्रावधान करना चाहिए। सारा देश जानता है कि वे वहां पर क्यों शहीद हुए। देश ने उनको जो डायरेक्शन दिया था, उसके अनुसार उन्होंने काम किया। उन्होंने शपथ ली थी कि हम जान का खतरा उठाकर भी हरमंदिर साहब की तरफ बन्दूक का मुंह नहीं करेंगे।

इसके अलावा आतंकवादियों, उग्रवादियों और अलगाववादियों की कार्यवाहियों से तीन सालों में जो 300 व्यक्ति शहीद हुए हैं, उनके परिवारों के लिए भी विशेष प्रावधान करना चाहिए ।

यह सही है कि जहां तक अर्थ व्यवस्था का प्रश्न है, पंजाब सब राज्यों से आगे रहा है । श्री सत्य साधन चक्रवर्ती ने सरकार की नीतियों की आलोचना की है । मैं बताना चाहता हूं कि 1980 मे जनता पार्टी ने एक जर्जरित अर्थ व्यवस्था हमे दी थी । सी. पी. आई. और सी. पी. एम. दोनों जनता पार्टी का समर्थन करते थे ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सी. पी. आई. ने उसका समर्थन नहीं किया ।

श्री राम प्यारे पनिका : इन लोगों के क्या सिद्धान्त हैं ? चौधरी चरण सिंह ने केवल दोहरी सदस्यता के प्रश्न पर जनता पार्टी को तोड़ा था । क्या आज आर. एस. एस. का प्रश्न नहीं है ?—आज भी वह प्रश्न है । लेकिन श्री वाजपेयी और चौधरी चरण सिंह को लगा कि हम लोगों का अस्तित्व समाप्त होने वाला है, इसलिए आज उनके द्वारा साम्प्रदायिकता और जातीयता का गठबंधन किया गया है । इसी आधार पर वे अगले चुनावों में वोट प्राप्त करना चाहते हैं ।

(व्यवधान)

जनता पार्टी के शासन ने देश की अर्थ-व्यवस्था को जर्जरित कर दिया था, उस अवधि में कृषि-उत्पादन में गिरावट आई थी, औद्योगिक उत्पादन की दर 1.4 परसेंट रह गई थी, जीवनोपयोगी चीजों का हर जगह अभाव था । इसके अलावा विदेशों में हमारी प्रतिष्ठा खत्म हो गई थी ।

(व्यवधान)

श्री जगपाल सिंह : मेरा पायंट आफ आर्डर है । चौधरी चरण सिंह इस सदन के माननीय सदस्य हैं और वह सदन में उपस्थित नहीं हैं । इसलिए उनका नाम लेकर डीफेमेटरी भाषण देने की इजाजत न दें ।

(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : I will go through the record. If there is anything unparliamentary or derogratory to the member of the House, I will see that.

SHRI JAGPAL SINGH : Choudhary Charan Singh is a member of the House. He is not present at this time in the House. Therefore, he cannot criticise Choudhary Charan Singh.

(*Interruptions*)

श्री राम प्यारे पनिका : उनको क्लैरिफिकेशन देने का मौका मिलेगा ।

श्री जगपाल सिंह : पंजाब पर चर्चा हो रही है, जनता पार्टी पर नहीं ।

MR. CHAIRMAN : It is not unusual to take the names of other Members of this House but if there is any derogratory remark, if there is any insinuation against the Member, I would definitely look into the records but he cannot be precluded from taking his name. He can take your name. He can take his name also.

श्री राम प्यारे पनिका : मैं चौधरी साहब का बड़ा सम्मान करता हूं लेकिन उनके कार्यों को यहां पर बतलाना आवश्यक है ।

MR. CHAIRMAN : You were also interrupting when other Members speak and they are now paying you in the same coin.

SHRI RAM PYARE PANIKA : No. Not at all.

MR. CHAIRMAN : I know it.

श्री राम प्यारे पनिका : मैं बहुत सही बात करता हू । मैं यह कह रहा था कि जनता

पार्टी के शासन काल में इस देश की अर्थ-व्यवस्था बहुत ही जर्जर हो गई थी । इस देश की प्लानिंग को रोलिंग प्लान के नाम पर इन्होंने बन्द कर दिया था लेकिन हमारी पार्टी के सत्ता में आने के बाद, बावजूद बाढ़ और सूखे के और बावजूद पंजाब में इस प्रकार की स्थिति इन लोगों द्वारा पैदा किए जाने के, इस साल 15 करोड़ टन गल्ला देश में पैदा हुआ है जो कि एक रिकार्ड है ।

(व्यवधान)

आज आवश्यकता इस बात की है कि पंजाब में सद्भावना का वातावरण पैदा किया जाए और हमारी प्रधान मन्त्री के शब्दों में वहां के लोगों के दिलों में जो घाव पैदा हुआ है उसको भरने की नितान्त जरूरत है ।

जगपाल सिंह जी ने सन्ता सिंह का जिक्र किया है । मेरा निवेदन है कि हमारी सरकार ने प्रयास किया कि स्वर्ण मंदिर का पुनर्निर्माण हो लेकिन कोई भी सामने नहीं आया और तब संतासिंह जी वालंटरी कार-सेवा करने के लिए सहमत हुए और उन्होंने इस कार्य को अपने हाथ में लिया । उसके बाद अब अकाली दल, पांच जत्थेदार और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने खड़कसिंह को यह काम सौंपा है, लेकिन उन्होंने बहुत ठीक कहा है कि जब तक वहां पर सामान्य स्थिति नहीं होगी, जब तक वहां से मिलिट्री और पैरा-मिलिट्री फोर्सेज नहीं हटाई जातीं तब तक वे कार-सेवा का काम नहीं कर सकते हैं । श्रीमन्, इनके नेता चौधरी चरण सिंह भी नहीं चाहते हैं कि स्वर्ण मंदिर से सेना हटाई जाए जब तक कि सामान्य स्थिति नहीं आ जाती लेकिन ये यहां पर अपने नेता के ही विरोध में बोल रहे हैं ।

श्री जगपाल सिंह : यह गलत इन्टरप्रिटेशन है । मैंने कहा है कि जितनी जल्दी हो सके वहां पर सामान्य स्थिति लाई जाए । लम्बे समय तक वहाँ पर फौज को रखना देश के लिए हानिकारक होगा ।

(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : How can I allow two Members to speak at the same time ? I do not allow this.

Only one Member can speak at one time. How can I allow both the Members to speak at once ? I will not allow unless he yields.

श्री जगपाल सिंह : मेरा पर्सनल एक्सप्लेनेशन है ।

सभापति महोदय : उन्होंने कोई पर्सनल बात कही नहीं है । फिर पर्सनल एक्सप्लेनेशन भी बाद में किया जा सकता है, अभी नहीं ।

श्री राम प्यारे पनिका : मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि हमारे देश की अर्थ व्यवस्था निरन्तर सुधरती गई है । इसका एक प्रमाण यह है कि आई. एम. एफ. से जो लोन हमें लेना था उसको भी हमने लेना बन्द कर दिया । इस प्रकार आप देखेंगे कि देश की अर्थ व्यवस्था अच्छी हुई है । पंजाब हमारे देश का एक हिस्सा है लेकिन वहां की हालत पिछले ढाई सालों में बहुत खराब कर दी गई । जनता पार्टी के शासन काल में इनके विदेश मन्त्री ने विदेशों में भी इस देश की प्रतिष्ठा को गिराया था । लेकिन हमारी सरकार देश की प्रतिष्ठा को उठवाते हुए पंचवर्षीय योजना के सारे लक्ष्यों को प्राप्त करती जा रही है । हमारी सरकार 18 खरब का नया प्लान बनाने जा रही है । हमारी सरकार ने हर दृष्टि से देश की प्रतिष्ठा बढ़ाई है । श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब विदेश मंत्री थे तो ज्यादातर वे विदेशों में ही रहते थे लेकिन जब हमारी सरकार आई तो विदेश के लोगों में यह कंपटीशन होने लगा कि इन्दिराजी की सहानुभूति कौन प्राप्त करेगा ।

हमारे कार्यक्रमों की एक दिशा थी, हमारा एक लक्ष्य था, उसी लक्ष्य पर चल कर हमने सफलता प्राप्त की। जैसी कि कहावत है—कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा—ये सब विभिन्न पार्टियां एक होने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन देश की जनता ने इनको पहचान लिया है, इसलिए ये कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं।

इन चन्द शब्दों के साथ माननीय वित्त मंत्री जी ने जो मांग रखी हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं। उग्रवादी लोगों की वजह से जो हमारी अर्थ व्यवस्था बिगड़ गई थी, नहर को काट दिया गया, उसके लिए केन्द्रीय सरकार को बजट में थोड़ी अलग से धनराशि देनी चाहिए। यह मैं कह सकता हूं कि मुट्ठी भर 15-20 प्रतिशत लोगों के कारण ही वहां पर शेष 85 प्रतिशत लोगों को परेशानी हो रही है। इसलिए केन्द्रीय सरकार को थोड़ा-सा हाथ इस तरफ भी बढ़ाना चाहिए, ताकि बिगड़ी हुई व्यवस्था सुधर सके।

प्रो० अजीत कुमार मेहता (समस्तीपुर) : सभापति महोदय, अभी जो मैंने भाषण सुना, उससे पता चला कि बिना पंजाब के बारे में कुछ बोले हुए पंजाब के बजट पर कैसे डिस्कशन हो सकता है। क्या पंजाब भारत का भाग है, इसीलिए सारे भारत की हम चर्चा कर लें और चूंकि पंजाब एक भाग है, इसलिए पंजाब की चर्चा हो गई है।

सभापति जी, पंजाब के श्वेत-पत्र पर चर्चा होने के समय में बहुत सुझाव दिए गए, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं। किन्तु मैं इतना अवश्य कहूंगा कि पंजाब की समस्या का जो निदान निकाला गया है, वह वास्तविक और स्थायी निदान नहीं है। वहां पर केवल प्रशासनिक समस्या ही नहीं थी, वहां राजनीतिक समस्या थी, तात्कालिक निदान वहां की विधि-व्यवस्था के बिगड़ने पर जो प्रयत्न किया गया, उससे पंजाब की समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। समस्या अभी भी ज्यों की त्यों है, हमें उसका राजनीतिक समाधान खोजना होगा।

जून के प्रथम सप्ताह में वहां फौजी कार्यवाही की गई, उसकी आवश्यकता थी और ठीक समय पर हुई। परन्तु क्या फौज की वहां उपस्थिति अभी तक आवश्यक है ? इस पर हमें सोचना होगा। पाकिस्तान और अन्य विकासशील देशों का उदाहरण हमारे सामने है। हम नागरिक प्रशासन के लिए सेना को निमंत्रित करें तो उसका नतीजा यह निकलता है कि सेना ही नागरिक प्रशासन पर अधिकार जमा लेती है। पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू है, सब जगह लागू होता है, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है कि सेना के अधिकारी लोग राज्यपाल के सलाहकार नियुक्त किए गए हों। परन्तु पंजाब में ऐसा हुआ। कोई भी परिस्थिति हो राज्यपाल के सलाहकार के रूप में सैनिक अधिकारियों की नियुक्ति नहीं होनी चाहिये। पंजाब में सैनिक अधिकारियों की जो नियुक्ति हुई है, इसका क्या परिणाम निकलेगा ? सैनिक अधिकारियों के अन्दर भी नागरिक प्रशासन के प्रति लिप्सा और तृष्णा पैदा होगी। जिस तरह से हम किसी शेर को आदमी के खून का स्वाद दिलायें तो वह उसके बाद नरभक्षी हो जाता है।···

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : प्रोफेसर साहब बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, इस किस्म की बात उनको नहीं बोलनी चाहिये। अब तक कई जनरल्ज़ गवर्नर हुए हैं···

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली): रिटायर होने के बाद।

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : कार्यरत सलाहकार नियुक्त नहीं हुए हैं।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : इसमें क्या गलत बात है। हैदराबाद में जनरल जे०एन० चौधरी गवर्नर थे।

प्रो० अजित कुमार मेहता : हैदराबाद की स्थिति भिन्न थी, वहां पंजाब जैसी स्थिति नहीं थी। हैदराबाद अपने को स्वतन्त्र घोषित करना चाहता था, लेकिन पंजाब में ऐसी बात नहीं है। आप गलत उदाहरण न दिया करें।

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : गलत उदाहरण तो आप दे रहे हैं।

प्रो० सत्यदेव सिंह : प्रो० मेहता ने बिल्कुल गलत उदाहरण दिया है...

प्रो० अजित कुमार मेहता : प्रो० सत्यदेव सिंह ऐसी जगह से आते हैं जहां शब्दों की भाषा लोग नहीं समझते हैं, वहां के लोगों को समझाने के लिये किसी अन्य भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसलिये वह हमारी बात नहीं समझेंगे।

मैं निवेदन कर रहा था कि पंजाब में सैनिक अधिकारियों की नियुक्ति राज्यपाल के सलाहकार के रूप में हुई है, उन पर विधि-व्यवस्था तथा न्याय जैसे मामलों की जिम्मेदारी डाली गई है, जो कदापि उचित नहीं है। सेना के जवान भी हमारी ही तरह के आदमी हैं, उनके अन्दर भी हमारी ही तरह लिप्सा और तृष्णा जागृत हो सकती है...

प्रो० सत्यदेव सिंह : उनमें राष्ट्रभक्ति ज्यादा है।

प्रो० अजित कुमार मेहता : मैं आपकी बात को इगनोर करूंगा। मैं कह रहा था कि सेना के जवान भी हमारी तरह के साधारण आदमी होते हैं, उनमें भी हमारी तरह लिप्सा और तृष्णा पैदा हो सकती है। हमारे लिये यह कदापि उचित नहीं है कि उनकी इस भावना को जागृत करने में हम सहायक बनें। सेना के जवानों की एक विशिष्टता यह होती है कि वे अनुशासन-बद्ध होते हैं तथा सामान्य समाज से अलग रखे जाते हैं। लेकिन जब उनको इस तरह के नागरिक प्रशासन के कामों में लिया जाता है तो वह अनुशासन-बद्धता एक तरह से समाप्त हो जाती है और वे एक साधारण नागरिक की तरह के बन जाते हैं। साधारण प्रशासन में जो भ्रष्टाचार है, उसका प्रभाव उन पर भी पड़ता है और वे भी भ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिये हमको अपनी सेना को इन कार्यों से अलग रखना चाहिये...

प्रो० सत्यदेव सिंह : प्रो० मेहता सदन में भ्रम पैदा कर रहे हैं।

प्रो० अजित कुमार मेहता : दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सेना की वहां पर अनिश्चित काल तक उपस्थिति सिखों के मन में अस्थायी क्षोभ पैदा कर सकती है। सेना को न स्थानीय समस्याओं का ज्ञान होता है और न नागरिक प्रशासन का अनुभव होता है। इसलिये नागरिक प्रशासन में लगा देने के बाद स्थानीय समस्याओं का समाधान न कर पाने के कारण वहां के नागरिकों में असंतोष पैदा हो सकता है। लोग ऐसा महसूस कर सकते हैं कि वहां पर सेना का शासन है। वे देश के अन्य भागों की तरह से नहीं है, बल्कि देश में उपनिवेश की तरह से है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं—जब हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था तो बंगलादेश, जो कि उस समय पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, सेना के नागरिकों के मन में यह भावना घर कर गई कि वे तो दूसरे दर्जे के नागरिक हैं और इस कारण से उनके मन में अलगाववादी भावना पैदा हो गई। अन्ततः पाकिस्तान का वह हिस्सा पाकिस्तान से अलग हो गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यदि सेना को नागरिक प्रशासन

के कार्य में लगाया जाएगा तो उससे ऐसा खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसलिए सेना को वहां लम्बे अर्से तक नहीं रखा जाना चाहिए।

मेरा यह भी कहना है कि हमें राज्य सरकार की दक्षता और विश्वसनीयता को लौटाना होगा। सेना के वहां रहते यह सम्भव नहीं हो पायेगा।

सभापति जी, वहां पर सेना को ज्यादा दिनों तक रखने के पीछे एक मंशा यह भी दिखाई पड़ती है कि सिखों के मन में हिन्दुओं के प्रति क्षोभ है और सेना को वहां से हटा लेने पर उनकी जान को खतरा उत्पन्न हो जायेगा। हिन्दु संभवत: वहां अपनी रक्षा न कर पायें। परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि वहां परिस्थिति यह है कि सिखों का क्रोध हिन्दुओं के प्रति नहीं है, बल्कि सरकार के प्रति है। इसीलिए सौहार्द्रपूर्ण वातावरण बनाने के लिए भी वहां से यथाशीघ्र फौज की वापसी जरूरी है। कम-से-कम स्वर्ण मन्दिर के परिसर से तो यह होनी ही चाहिए।

सभापति जी, भिण्डरावाले की मौत से पंजाब के उग्रवादी छिन्न-भिन्न हो चुके हैं। अब हमें इस स्थिति का लाभ उठाना चाहिए। हमारे सामने दो विकल्प हैं—या तो उन उग्रवादियों को एकदम समाप्त कर दें अथवा यह सोचें कि ये उग्रवादी सिख सिखों के साधारण नौजवान थे जो भिण्डरावाले के दुष्प्रभाव में आकर गलत रास्ते पर चल पड़े थे और उनको सही रास्ता दिखाकर उन्हें सुधारा जाए। मैं समझता हूं कि दूसरा विकल्प अधिक सहायक और समस्या के समाधान करने में अधिक सार्थक सिद्ध होगा। इस विकल्प को अपनाना चाहिए।

अब मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। यह सर्वविदित है कि पंजाब के दो वरिष्ठ नेताओं में जो कि पंजाब के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री रहे हैं, आपसी मतभेद के कारण इस समस्या को बढ़ावा मिला। इसका परिणाम इतना बुरा निकला कि पंजाब में अलगाववादी ताकतें खड़ी हो गईं।

प्रो० सत्य देव सिंह : अब तो भूतपूर्व मुख्य मंत्री राष्ट्रपति हो गये हैं, अब तो वे वहां की राजनीति में नहीं हैं।

प्रो० अजीत कुमार मेहता : मैं भूतपूर्व मुख्य मंत्री कहा है, मैंने किसी का नम नहीं लिया है। हमारा सुझाव है कि इन दोनों भूतपूर्व मुख्य मत्रियों के समर्थकों के बीच का जो मतभेद है, जो झगड़ा है, उसको कम-से-कम दूर करा देना चाहिए। यह मतभे और झगड़ा इतना अधिक नहीं बढ़ने देना चाहिए जिससे कि अलगाववादी ताकतों को बल मिले।

मेरा दूसरा सुझाव है कि सिखों के धर्मिक स्थान अकाल तख्त के विषय में व्यवहारिकता से काम लेना चाहिए। यह मैं मानता हूं कि कार-सेवा करने का अधिकार सभी को है। परन्तु वह कार सेवा सुनियोजित रूप से सिखों की संस्था के माध्यम से ही करवाई जाए। इससे सिखों को संतोष होगा। बाबा सेवा सिंह जी द्वारा कार-सेवा करने से कन्फ्रन्टेशन की स्थिति पैदा हो गई है और प्रबन्ध समिति ने यहां तक घोषणा कर दी है कि उनके द्वारा किए गए काम को वह गिरा देंगे। इस तरह की कन्फ्रन्टेशन की स्थिति पैदा नहीं होने देनी चाहिए।

सभापति महोदय : ये सारी बातें तो पंजाब पर हुई चर्चा के समय कह दी गई हैं। अगर आपको पंजाब के बजट पर कुछ बोलना है तो कहिये।

17.00 hrs.

प्रो० अजीत कुमार मेहता : सभापति जी, मैं कह रहा था कि पंजाब में जो स्थिति है,

उसमें जल्दी से-जल्दी सुधार लाना चाहिए । अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि पंजाब में बड़ी तोड़फोड़ हुई है । बहुत सी जानें गई हैं । इसलिए आवश्यक है कि पुर्नवास के लिए और अधिक राशि का प्रवधान किया जाना चाहिए । जिन परिवारों ो क्षति हुई है, उनको अधिक-से-अधिक सायता दी जा सके ।

17.00 hrs

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

पंजब की समस्या प्रशासनिक समस्या नहीं थी । ह एक राजनीतिक समस्या थी । इस समस्या का निदान सभी दल के लोग मिल-बैठ-कर क । आनन्दपुर साहब के प्रस्ताव को भूल जाइये। विपक्षी दलों का उसको कभी समर्थन प्राप्त हीं हुआ । इसलिए उस प्रस्ताव को भूल कर मस्या का समाधान निकालिए । सभी उग्रवदियों को हम मुख्य धारा से काट पायेंगे और समस्या का समाधान हो जाएगा । इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं क आपने मुझे बोलने का समय दिया ।

MR. DEPUTY SPEAKER : I may inform th Hon. Members that one hour has been abtted for this bill. We have aleady taken 1-1/2 hours. We have got the nxt item-Half-an-Hour discussion. Therefore Iwould request the Hon. Members to be tief in speech and I am allowing each Hon. Iembers 5 minutes. Now, Mr. Harish Lumar Gangwar to speak.

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : सभापति जी, पंजाब के लोग बड़े बहादुर होते हैं । अपनी बहादुरी का सिक्का उन्होंने हिन्दुस्तान-भर में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जमाया है । सबसे पहले पंजाब को धक्का लगा जब हिन्दुस्तान के टुकड़े होकर पाकिस्तान बना । बहुत बर्बादी हुई । लेकिन पंजाब के लोगों ने अथक परिश्रम करके आज उसको हिन्दुस्तान का नम्बर एक का राज्य बना दिया है । उन्होंने उद्योग धंधे स्थापित किए । खेती को अच्छा किया । फौज में सबसे अधिक नौजवान पंजाब ने दिए, जिन्होंने हमारी सेवा की । पंजाब उस धक्के को सहन कर गया जो विभाजन में हुआ । उस वक्त पंजाब जल रहा था । आज दूसरा धक्का लगा है इन आतंक-वादियों से । इसके लिए पूरी सिक्ख कौम को दोष देना बहुत बुरी बात होगी । इससे अधिक कोई गलत बात नहीं हो सकती ।

यह वह कौम है, जिसने कभी हाथ नहीं फैलाया और भीख नहीं मांगी और हिन्दुस्तान को आगे बढ़ाने में हमेशा मदद की । मैं इस बात में नहीं जाना चाहता कि गलती किसने की है । मैं यह मांग करता हूं कि एक उच्चस्तरीय आयोग बनाया जाए, इन तमाम घटनाओं की जांच करने के लिए, जिससे वास्तविकता का पता चल सके । श्वेत-पत्र जारी करने या स्पीचेज देने से कुछ नहीं होता है । उच्चस्तरीय आयोग बैठने से पता चलगा कि किन कारणों से यह सब हो रहा है । जो लोग मारे गए हैं, चाहे वह फौज के हों या आम जनता के लोग हों, उन सबको ज्यादा-से-ज्यादा पूरा मुआवजा मिलना चाहिए अगर उनके मकानों या जायदाद का नुकसान हुआ है तो उसकी क्षतिपूर्ति भी आपको करनी चाहिए जैसा कि और दगाग्रस्त क्षेत्रों म आप किया करते है । हमारे जिन फौजियों ने अपनी जान पर खेलकर अपने काम को पूरा किया, उनको भी भारी रकम मुआवजे की उनके परिवारों को देनी चाहिए । लोकप्रिय सरकार की स्थापना शीघ्र-से-शीघ्र की जानी चाहिए । जब तक रिप्रिजन्टेटिव गवर्नमेंट वहां नहीं होगी तब तक काम नहीं चलेगा । वार्ता का दौर फिर से होना चाहिए और राजनैतिक मुद्दा बनाकर राजनैतिक रूप से समस्या का समाधान करना चाहिए । अगर फौज ज्यादा दिनों तक वहां रहेगी तो जैसा और जगह होता

है, वही होगा। यह बात तो निर्विवाद सत्य है कि सीमा पर से हथियार आए। इसलिए भारत और पाकिस्तान की सीमा को और टाइट करना चाहिए जिससे फिर वहां हथियार न आ सकें। यह साबित करना मुश्किल होता है कि किस देश के जरिए उनको लाया गया। जान भी जाएं तो भी नाम लेना मुश्किल होता है। पंजाब से लेकर राजस्थान तक जितनी सीमा पाकिस्तान से लगी हुई है, उस पर कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए। अखबारों में छपा है कि आतंकवादियों के साथ-साथ सी० आई०ए० का भी इसमें हाथ है। इसकी जांच होनी चाहिए। यह पता लगाना चाहिए कि कौन-कौन व्यक्ति इसमें इन्वाल्वड हैं। मैं यह कह सकता था कि सरकार को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि वह अटर फैल्योर रही है। चार-पांच महीने के बाद तो आप खुद ही हट जायेंगे। बहुत बार आप कहते हैं कि ठीक समय पर इलाज कर दिया। पैर में दर्द शुरू हुआ तो दर्द की गोली नहीं दी, वह फोड़ा बन गया। उसका इलाज नहीं हुआ तो डाक्टर ने कहा कि पैर काटने से काम चलेगा। आपने पैर काट दिया। यह कौन-सा इलाज हुआ ? अगर शुरू में इलाज कर देते तो यह दर्द ठीक हो सकता था। आपने एक टांग काटकर पूरे पंजाब को पंगु बना दिया। अभी पनिका जी ने कहा कि साम्प्रदायिक शक्तियों के साथ विरोधी दल वाले मेल करते हैं।

मैं यह पूछना चाहता हू कि केरल में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर किसने सरकार बनाई, बम्बई में शिव सेना के साथ किसने समझौता किया। अकाली दल के साथ मिलकर पंजाब में किसने सरकार बनाई, अकालियों को बढ़ावा दिया, किसने उनके साथ समझौता किया—कांग्रेस आई ने और इंदिरा गांधी की सरकार ने। इतना ही नहीं, त्रिपुरा में आनन्दमार्गियों के साथ चुनाव समझौता किसने किया और अब परसों या उससे एक दिन पहले अखबारों में निकला है कि आजकल श्रीमती इन्दिरा गांधी की आर. एस. एस. के चीफ श्री देबराज से बात हो रही है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, अलबारों में निकला है। इस समय यहां पर राम प्यारे पनिका जी बैठे नहीं है, शायद उन्होंने पिछला इतिहास नहीं पढ़ा। सिर्फ बोलने से मतलब है। लेकिन साम्प्रदायिक शक्तियों के साथ, वोट की खातिर, सरकार बनाने के लिए कांग्रेस आई और श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जितने समझौते किए हैं, उतने पहले शायद कभी नहीं हुए और जवाहर लाल नेहरू इससे हमेशा अलग रहे। इसलिए श्रीमन् मैं कहना चाहता हूं कि आप सबसे बड़े साम्प्रदाकि हैं, साम्प्रदायिक शक्तियों के साथ आप समझौता करते हैं और इसी कारण हिन्दुस्तान में साम्प्रदायिकता बढ़ती जा रही है।

(व्यवधान)

MR. DEPUTY SPEAKER : If everybody continues like this, will have to call the Minister to reply. Already 1 hour is over.

श्री हरीशकुमार गंगवार : हाफ-ए-मिनट सर। अब मैं कार-सेवा के बारे में थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूं।

MR. DEPUTY SPEAKER : I do not know whether anybody has gone through this Budget. You are not speaking on budget. All other things are being said which are quite irrelevant to the subject. I am quite helpless. How can I convince Shri Gangwar ?

SHRI HARISH KUMAR GANGWAR : I am speaking on the budget. Please pick up my speech and delete all the lines which are not relevant. Have you listened to Shri Ram Pyare Panika's speech, Sir ? Is it relevant ?

MR. DEPUTY SPEAKER : I am going to ask the Minister to reply. I am not going

to allow anybody to speak. One hour is over.

श्री हरीश कुमार गंगवार : किसने इस देश में साम्प्रदायिक शक्तियों के साथ समझौता करके उनको बढ़ावा दिया ।

(व्यवधान)

अब मैं कार-सेवा के सवाल पर श्रीमन् कुछ कहना चाहता हूं । जब कार-सेवा का मामला आया, तो संता सिंह जी के जरिए, यह सरकार कार-सेवा करा रही है । उधर गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति की ओर से यह झगड़ा मचाया जा रहा है कि संता सिंह जी कार-सेवा नहीं कर सकते, हमें इस सेवा को करना चाहिए, लीगली कार-सेवा करने का हक हमारा है । श्रीमन् ऐसा लगता है, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर, मुख्य मंत्रियों या दूसरे मन्त्रियों के लिए ट्रकों में लोगों को ला-लाकर भीड़ इकट्ठी कराई जाती है, उसी तरीके से ट्रकों में इधर-उधर से लोगों को लाकर वहां भी भीड़ जुटाई जा रही है, ताकि कार-सेवा करवाई जा सके । मैं आपसे कहता हूं कि आप जल्दी ही इस समस्या पर समझौता करवाइये ताकि झगड़े का अन्त हो सके और मिलिटरी को वहां से जल्दी-से-जल्दी हटाया जा सके ।

MR. DEPUTY SPEAKER : Now, the Minister will reply. One hour has been allotted for Punjab Budget. Nobody speaks on budget. Everybody speaks on politics. We are very much behind the schedule with regard to the legislative business We have not done anything else.

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY SPEAKER : Of course, other speeches which are very useful are made. If every Member can assure me that we will speak only on the Budget of Punjab I will allow all of you. Everyone shall not speak for more than three minutes. Politics is not the matter under discussions. We are discussing Punjab Budget because there is no Government there and it is Centre's work. I want your suggestions on that.

What do you want him to delete, what do you want him to add; on what points you want the Minister to reply, and whether you expcet him to delete or add anything. Am I to educate you ? You are all learned, knowledgeable and Honourable Members of this great House.

If anybody speaks on anything other than the Punjab Budget, I will stop him.

(*Interruptions*)

They are irrelevant to the subject matter of discussion.

Now Shri Sunder Singh. He will speak only on Punjab Budget, for three minutes. Anything other than that, shall be treated as irrelevant.

I am not concerned with any side, or any Member. There should be some seriousness in the discussion. We cannot find a solution to your political issues and political problems. This House is not intended for that purpose.

श्री गिरधारी लाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई न्याय है कि उधर के लोग आधे घण्टे तक बोलें और अब आप हमें 3 मिनट दे रहे हैं ?

MR DEPUTY SPEAKER : Please sit down.

श्री सुन्दर सिंह (फिल्लौर) : डिप्टी स्पीकर साहब, पंजाब के मुताल्लिक मैं कहना चाहता हूं कि टैरेरिस्ट्स ने जो वहां काम किया है, इससे 2-3 साल से वहां बदअमनी रही है । गरीब लोग वहां पर सहमे हुए थे, वहां इण्डस्ट्रीज में कोई काम नहीं हुआ, इण्डस्ट्रियलिस्ट्स वहां से भाग रहे हैं । वहां पंजाब में जो इस वक्त गड़बड़ हुई है, उसकी वजह से वहां हालात बहुत खराब हैं । वहां गरीब जमींदार और गरीब किसान बहुत खराब

हुए हैं, उनका बहुत नुकसान हुआ है। गवर्नमेंट को चाहिए कि ज्यादा-से-ज्यादा पैसा उनके लिए एलाट करे।

जहां तक हरिजनों का ताल्लुक है वहां गरीब किसान काम करते हैं जिनकी जमींदारों से भी ज्यादा हालत खराब है। सरकार को हरिजनों के लिए 40 करोड़ रुपया एलाट करना चाहिए जिससे वह वहां जाकर आबाद हों। जो बड़े जमींदार हैं, वह तो शहर में आकर खाते हैं, जो हमारे गरीब आदमी हैं, वह काम करते हैं खेतों में, उनके लिए सहायता करनी चाहिए।

मैं खुद भी एक जमींदार हूं, मैंने खुद ने काश्तकारी की है। अगर आप पंजाब में लैंड रिफार्म करते तो आपके जमींदारों के बच्चे भी हमारी तरह रोटी के लिए भागते। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि वह बड़े बहादुर हैं। वह बड़े बहादुर नहीं हैं, उन्होंने पंजाब का सत्यानाश किया है।

यह जो बड़ी भारी कान्फ्रेंस यू.एस.ए. में हुई है, न्यूयार्क में वहां के बड़े-बड़े आदमी हिन्दुस्तान के बरखिलाफ नारे लगाते रहे हैं। वहां कहते हैं कि पंजाब अलग चाहिए। वह इन्दिरा जी के बरखिलाफ बोलते हैं। मैं कहता हूं कि जो महात्मा गांधी और पं० जवाहर लाल नेहरू ने काम किये हैं, वे अमर रहें। आज वहां पर लोग हिन्दुस्तान का सत्यानाश करना चाहते हैं। छम्ब जौड़ियां में हमला हुआ तो हरिजन वहां गए थे।

राजपूत और बड़े जमींदार वहां नहीं गए थे। वहां पर जो मरे हैं, वे सब हरिजन थे। हिन्दुस्तान में मन्दिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों के पास बहुत जमीनें हैं। अगर वे जमीनें गरीबों को दे दी जाएं तो उनकी हालत सुधर सकती है।

Where should you seek for God ? Are not the poor, the miserable and the down-trodden God ? Worship them first. I do not believe in a God and religion who cannot wipe out tears from the widow's face and cannot bring morsel of food to the orphans mouth.

महात्मा गांधी मन्दिर, मस्जिद या गुरुद्वारों में नहीं जाते थे, क्योंकि वह समझते थे कि परमात्मा हर जगह है। इकबाल ने कहा है :

मन्दिर और मस्जिद में समझा है कि तू खुदा है,
खाके-वतन का मुझको हर जर्रा देवता है।

कहा जाता है कि पंजाब से आर्मी को विदड्रा (withdraw) कर लेना चाहिए। तो फिर लोगों को बचाने का काम कौन करेगा ? मैं कहना चाहता हूं कि जब तक पंजाब की हालत बिल्कुल ठीक न हो जाए, तब तक आर्मी को वहां पर रहना चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा :—

"The better mind of the world desires today not absolutely independent States warring one against another, but a federation of a friendly interdependent States."

हर एक आदमी को उग्रवादियों की मुखालिफत करनी चाहिए थी, लेकिन आपोजिशन वाले उनकी मदद कर रहे हैं। इससे उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। यदि पंजाब में आर्मी एक्शन लेने पर श्रीमति इन्दिरा गांधी की स्पोर्ट करते तो उनको वोट मिल जाते। लेकिन अब उनको कोई वोट नहीं मिलेगा।

श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हम संसद में पंजाब का बजट डिसकस कर रहे हैं, जबकि 6 अक्तूबर को वहां पर राष्ट्रपति शासन समाप्त होगा। अब आपरेशन ब्लूस्टार वहां पर समाप्त

हो गया है और राज्य नार्मल्सी की ओर बढ़ रहा है, इसलिए अब वहां पर राष्ट्रपति शासन को समाप्त करके लोकप्रिय शासन की स्थापना करनी चाहिए या निलम्बित विधान सभा को डिजाल्व कर देना चाहिए।

पंजाब एक ऐसा राज्य है, जो कृषि, उद्योग और अन्य क्षेत्रों में देश-भर में सबसे आगे था। वहां की पर-कैपिटा इनकम देश के सभी भागों की तुलना में ज्यादा है। लेकिन पिछले तीन वर्षों में उसकी व्यवस्था जर्जर हो गई है, आर्थिक गिरावट आ गई है और केन्द्र सरकार की ओर से उसको आर्थिक सहायता देकर खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है।

आज वहां की आर्थिक स्थिति बड़ी भयावह, दर्दनाक और गम्भीर बन गई है। यदि सरकार ने पहले से ही ऐक्शन लिया होता तो यह नौबत न आती। पनिका जी ने चौधरी चरणसिंह और वाजपेयी जी का नाम लिया लेकिन मैं उनको बताना चाहूंगा कि बी.जे.पी. के तीस हजार लोगों ने इस बात की मांग की थी कि पंजाब में फौजी आपरेशन की आवश्यकता है पर आपकी सरकार की समझ में नहीं आया।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, पंजाब के जालंधर, अमृतसर, लुधियाना आदि जो शहर हैं वह औद्योगिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं परन्तु उनकी हालत बड़ी दयनीय बन गई है। एक करोड़ तो नगरपालिका में ठेकेदारों का बकाया है जोकि मार्च तक उन्हें मिल जाना चाहिए था। पूंजी से जो आय होती थी उसमें भी 50 परसेंट की गिरावट आई है। इतनी बदतर स्थिति आज वहां पर हो गई है। जालंधर में एशिया की सबसे बड़ी री-रोलिंग मिल है लेकिन उसका काम भी ठप्प है। इसी प्रकार से लुधियाना में वूलेन होजरी का सबसे बड़ा उद्योग है लेकिन वह भी टप्प पड़ा है। यही स्थिति अन्य जगहों की भी है। सरकार इस स्थिति को सुधारने के लिए तुरन्त कार्यवाही करे।

मेरा यह भी सुझाव है कि वहां पर सैनिक कार्यवाही से जो बरबादी हुई है या जो हत्यायें की गई हैं या जो बैंकें लूटी गई हैं या जो भी अन्य प्रकार भी बरबादी की गई है उसको सुधारने के लिए सरकार तुरन्त कार्यवाही करे। जो भी जवान मारे गए हैं उनके आश्रित परिवारजनों को एक-एक लाख रुपए का तुरन्त मुआवजा दिया जाए तथा साथ-ही-साथ राजस्थान नहर के किनारे जमीनें देकर प्राथमिकता के आधार पर उनको बसाया जाए। इसी प्रकार से जो अन्य बेकसूर लोग वहां पर मारे गए हैं उनके आश्रित परिवारजनों को एक लाख रुपया दिया जाए। जिनकी उम्र 25 से 50 के बीच में थी और जो परिवार को चलाने वाले थे उनके लिए एक लाख का मुआवजा दिया जाए।

इसके साथ-साथ मेरा यह भी निवेदन है कि स्वर्ण मन्दिर परिसर के आस-पास जो 800 दूकानें बरबाद हो गई हैं, उन लोगों का पीड़ित संघ यहां पर आकर प्रधान मन्त्री से मिला था और उन्होंने मांग की थी कि उनकी भी मदद की जाए। इन 800 लोगों के जो परिवार हैं उनको तुरन्त बसाने की व्यवस्था की जाए तथा उनको उदारतापूर्वक मुआवजा दिया जाए। अनुग्रम भुगतान की व्यवस्था तो तुरन्त की जानी चाहिए। यदि आप उनको गोल्डेन टेम्पल के अगल-बगल अब न रखना चाहें सुरक्षा के दृष्टिकोण से तो कोई अलग मार्केट बनाकर उनको बसाने की व्यवस्था की जाए। इसी प्रकार से जितने भी उद्योग-धंधे बन्द हुए हैं उनको पुनः चलाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए। इसी प्रकार से जो वहां पर खेती-बाड़ी का काम बन्द हुआ है बिजली के अभाव में, वहां

पर 80 हजार ट्यूबवैल हैं और साढ़े चार करोड़ रुपये के बिजली के बिल का भुगतान बकाया है जिनके सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है उसको रोका जाए। पैकेज प्रोग्राम के आधार पर कृषि तथा औद्योगिक विकास के जो कार्यक्रम हैं उनको द्रुत गति से लागू किया जाए। साथ ही ला एण्ड आर्डर में सुधार लाया जाए ताकि फिर से पंजाब एक औद्योगिक प्रांत बन सके। वहां पर सामान्य स्थिति आ सके, इसके लिए आप हर प्रकार की कार्यवाही करें।

———

17.29 hrs.

HALF AN HOUR DISCUSSION

Power Requirements and Production

MR. DEPUTY SPEAKER : We will now take up Half-an-Hour discussion. It has been already announced from the Chair that we have to complete the items of business that have already been listed for today. Therefore, after the Half-an-Hour discussion we will continue.

SHRI HARIKESH BAHADUR (Gorakhpur) : How is it possible ?

MR. DEPUTY SPEAKER : I have already announced. It is up to you. This has already been announced before I came. After Half-an-Hour discussion we will take up Pondicherry budget also.

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष जी, आज की आधे घंटे की चर्चा अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है और जो देश पर बिजली संकट है, उसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। मेरे द्वारा 24 जुलाई को पूछे गए प्रश्न पर जो मन्त्री महोदय ने जवाब दिया था, उससे सम्बन्धित जो पूरक प्रश्न बचे थे, उसके सम्बन्ध में यह चर्चा होने जा रही है।

उस दिन राज्य मन्त्री जी ने अपने जवाब में कहा था कि इस देश में बिजली की आवश्यकता 156 बिलियन यूनिट की है। उसके एगेंस्ट में 140 बिलियन यूनिट बिजली पैदा हो रही है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक यदि 16 बिलियन यूनिट बिजली और पैदा हो जाए तो देश की आवश्यकतायें पूरी हो जायेंगी। उस प्रश्न के जवाब में मन्त्री जी ने विशेषज्ञों की आड़ ली और तीन-चार और बातों का जिक्र किया। पहली बात यह है कि बिजली की व्यवस्था करना, उपलब्ध कराना राज्य सरकार का काम है और केन्द्रीय सरकार का दायित्व नहीं है। फिर उन्होंने एक बात और कही, यह कहना सम्भव नहीं है कि कब तक मांग की पूर्ति हो जाएगी। मैं पहले, उपाध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान खींचना चाहूंगा कि जैसा कि मन्त्री जी ने कहा कि बिजली का उत्पादन 85 से 90 प्रतिशत आवश्यकता के अनुसार हो रहा है, यह आंकड़ा मन्त्री महोदय को किसने दिया है, किस आधार पर दिया है ? यह बात अभी भी मेरे दिमाग में नहीं बैठती है। जिस वक्त मन्त्री महोदय ने यह बात कही थी, तो विरोध पक्ष के लोगों ने उसका प्रतिवाद किया था। इन्होंने कहा था कि छः घण्टे बिजली मिलती है, कहीं सात घण्टे बिजली मिलती है और यह कहा था कि छः-सात घण्टे बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सम्बन्ध में, जिसका प्रतिवाद हम लोगों ने किया। मैं अभी पिछले दिनों अपनी कांस्टीचूयेंसी में गया था, वहां महुवा में को-आपरेटिव सोसाइटी का कोल्ड स्टोरेज है, जहां किसान अपना आलू का बीज स्टोर करता है।

मैं जब वहां गया तो मैंने उनसे इसके बारे में बात की। मैंने उनसे कहा कि मंत्री महोदय